प्रधान मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अविश्वास प्रस्ताव से विपक्षी दल के विचार जानने का मौका मिलता है। तीन वर्ष पूर्व जब इसी प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव मेरे पिता के विरुद्ध लाया गया तो उन्होंने कहा था कि जिन करणों से-विभिन्न विरोधी दल एकत्रित हुये हैं वह अक्रियात्मक है न कि क्रियात्मक। इस अक्रियात्मकता का पता इस प्रस्ताव पर जो भाषण हुये उनसे चलता है। चर्चा के बीच जो व्याखान हुये उनसे पता चलता था कि विरोधी दलों में उसी प्रकार की भिन्नता है, वह न केवल एक दूसरे की बात का खण्डन कर रहे थे अपितु उनमें कोई तथ्य तथा उद्देश्य नहीं था।

विरोधी दलों का कहना है कि अवमूल्यन के विषय में हम पर दवाब डाला गया है। हम जोरदार शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम पर कोई दवाब नहीं डाला गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने कुछ उपाय करने के लिए हमें परामर्श नहीं दिया। हमें हमारे अर्थशास्त्रियों ने भी परामर्श दिया था। हमने न केवल अपने अर्थशास्त्रियों से ही परामर्श लिया अपितु सरकार से बाहर के विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों से भी परामर्श बहुत पहले ले लिया था। एक विख्यात अर्थशास्त्री ने एक लेख में अवमूल्यन का समर्थन किया था। अवमूल्यन का फैसला एक दुखद् निर्णय था परन्तु यह एक ऐसा निर्णय था जो हमें लेना आवश्यक था। यह कहा गया है कि गत वष से चल रही गलत नीतियों के कारण ऐसा निर्णय किया गया है। यह सर्वथा असत्य है। कुछ परिस्थितियों का दबाव अवश्य था। वे परिस्थितियां थी हमारी सीमाओं पर आक्रमण तथा लगातार आक्रमणों के कारण तथा सूखे के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भारी दबाब। यह कदम जानबूझ कर उठाया गया था ताकि आर्थिक स्थिति और अधिक खराब न होने पाये। यह कदम विश्वास तथा दूरदर्शिता से लिया गया ताकि सरकार आर्थिक स्थिति पर काबू पा सके और हमारा विचार है कि इसके स्थायी तथा दीर्घकालीन प्रभाव हमारी अर्थव्यस्था को मजबूत तथा स्वजनित बनायेंगे।

हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि अवमूल्यन कोई जादू का डंडा है और यह कदम उठाते ही हमारे सारे विकार दूर हो जायेंगे और मूल्य बढ़ने से रोक दिये जायेंगे। मूल्य अभी नहीं बढ़ने लगे बल्कि यह पिछले दो या तीन वर्षों से बढ़ रहे हैं। मूल्यवृद्धि को रोकने के सब उपाय असफल रहे हैं। इसलिए अवमूल्यन से शीघ्र ही कोई सुधार नहीं हो जायेगा। यह एक ऐसा उपाय है जिसके साथ और कार्रवाई भी ठीक की जाये तो इस से हमें उन्नति करने का फिर अवसर मिल जायेगा जो कि हमारे काबू से बाहर की परिस्थिति होने के कारण रुक गयी थी।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने तर्क दिया कि यदि हम अपने विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लेते तो हमें रुपये के अवमूल्यन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परन्तु उन देशों को भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा जिन्होंने विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया है। रूस तथा युगोस्लाविया ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया और इसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई। भारत में भी यदि अवमूल्यन को ठीक प्रकार से अपनाया गया और अगली कार्यवाही ठीक प्रकार से की गई तो नई वस्तुओं का निर्यात बढ़ जायेगा। यह खेद की बात है कि आर्थिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी इस विषय पर विरोधी दल केवल भावुक टिप्पणी कर सके हैं और उन्होंने आर्थिक तर्क की बिल्कुल उपेक्षा की है जबकि इस स्थिति में केवल वही संगत था।

प्रस्तावक ने स्वदेशी भावना को फिर उत्पन्न करने की अपील की है। स्वदेशी भावना को मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय समझती हूं और ऐसा मैं कर रही हूं। अवमूल्यन का उद्देश्य भी स्वदेशी भावना को जागृत करना है।

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना इस सभा तथा सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। मूल्य अवमूल्यन के पश्चात् नहीं बढ़ने लगे। वह पहले बढ़ रहे थे तथा उस पर काबू पाना कठिन हो गया था। किसी प्रकार की आयातित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि के लिए अवमूल्यन उत्तरदायी नहीं है। मूल्यवृद्धि की समस्या को हमने सुलझाना है। कई दुकानें खोली गई हैं। अभी स्टोरों की संख्या पर्याप्त नहीं है। शीघ्र ही शहरी क्षेत्रों तथा देहाती क्षेत्रों में और ऐसे 'स्टोर' खोले जायेंगे।

जमाखोर तथा समाज विरोधी तत्वों पर न केवल दिल्ली और पंजाब में ही मुकदमा चलाया गया है अपितु अन्य राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। परन्तु जितना करना चाहिए था, उतना नहीं हो सका।

जहां तक अनुवर्ती कार्यवाही का सम्बन्ध है, विरोधी दल ने कोई अनुकूल सुझाव नहीं दिया है। जितने ठोस सुझाव दिये गये हैं उन पर अवश्य ही विचार किया जायेगा। कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने भी बहुत से सुझाव दिये हैं। उनपर पूरी तरह विचार किया जायगा। सब से महत्वपूर्ण बात तो जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना है। दूसरी मुख्य बात यह हैं कि हमें निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये और उन वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में उदारता बरतनी चाहिये जिन से निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलती हैं। किसी प्रकार कि विलास वस्तुओं के आयात में उदारता नहीं बरती जायगी।

चौथी योजना अनुवर्ती कार्यवाही पर आधारित है। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिस से हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास कर सके। सरकारी क्षेत्र के लिए 16,000 रुपये रखा गया है। किन्तु मैंने योजना को इस दृष्टि से नहीं देखा कि उस पर कितना रुपया खर्च होगा। योजना इतनी बड़ी होनी चाहिए जिस से न कवल विद्यमान औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जा सके बल्कि उत्पादन की कमी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में जो असन्तुलन पैदा हो गया है उसे ठीक किया जा सके जिसके कारण हमारी निर्भरता विदेशी सहायता पर बढ़ती जा रही है। स्वतंत्र दल के कुछ सदस्य छोटी योजना का समर्थन करेंगे। इस का परिणाम यह होगा कि गरीबी निम्नस्तर के लोगों से चिपटी रहेगी। ऐसी योजना से समाज के केवल पूंजीपतिवर्ग को लाभ होगा और हम आत्मनिर्भर नहीं हो पायेंगे। इस लिये सरकार सरकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है चाहे कोई व्यक्ति से पसन्द करता है या नहीं। हम ऐसे उपाय करेंगे जिस से आर्थिक प्रणाली में असमानता दूर ही जाये। यदि धन कुछ लोगों के पास एकत्र हो गया तो देश की स्थिरता विचलित हो जायेगी। योजना अथवा अर्थव्यवस्था निर्माण का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत बनाना है। योजना आयोग में तथा अन्य स्थानों पर मैंने इस बात पर जोर दिया है कि भूमिहीन कृषि श्रमिकों, आदिम जातियों, हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ऐसे वर्गों पर अब जितना ध्यान दिया जा रहा है उस से भी कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। **(अन्तबाधा)** :

श्री रामसेवक यादव: हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के लिए ठोस तथा यर्थात कार्यक्रम क्या है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : योजना अभी बनाई जा रही है। तैयार होने पर वह सभा में प्रस्तुत की जायेगी और माननीय सदस्यों को उस समय योजना की आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। योजना के मार्गनिर्देशनों का हवाला मैंने अभी दिया है।

हमें यह याद रखना चाहिए कि छोटे से छोटे और गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी विश्व में आशा और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। यह खेद की बात है कि प्रतिपक्षी सदस्य आज देश के लोगों के आत्म विश्वास और आशा को तोड़ रहे हैं।

हमारा यह विश्वास है कि वियतनाम में युद्ध जारी रहना विश्व शान्ति के लिए तथा भारत के लिए भी खतरा है। वियतनाम समस्या के शान्तिपूर्वक हल से हमारा महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। इस के लिए हम गम्भीरता पूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। कालीकट में मैंने कहा था कि हम उस बारे में कोई नई बाद नहीं कर सकते। अपने रेडियो भाषण में मैंने कोई नई बात नहीं कही है। वियतनाम के विषय में हमने अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

विरोधी सदस्य वियतनाम में मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे जो विचार यहां प्रकट कर रहे हैं ऐसे विचार उन देशों के नेताओं में से किसी ने भी व्यक्त नहीं किये है जिन देशों का मैंने दौरा किया है। एशिया अफ्रीका तथा यूरोप के कई देशों ने हमारे रवैये का स्वागत किया है।

श्री अ० कु० गोपलन द्वारा मेरे सुझाव की अलोचना लगभग वैसी ही है जैसी कि पैकिंग रेडियो ने की है। चीन ही एक मात्र देश है जिसने मेरे सुझावों को प्रत्यक्ष रुप सें रद्द कर दिया है। वियतनाम की समस्या एक जटल समस्या है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इसका कोई सैनिक हल नहीं हो सकता और हमारी सहानुभूति वियतनाम की जनता के साथ है।

ताशकन्द घोषणा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध से दोनों देशों को लाभ होगा। हम यह नहीं मानते कि हमारे बीच तनाव का मुख्य कारण काशमीर है। यह तो मूल रोग का एक चिन्ह मात्र है। मैं पाकिस्तान को आश्वासन देती हूं कि हम किसी भी मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

सरकार देश की रक्षा करने के दायित्वों के प्रति सजग है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि काशमीर में उदडंता पूर्वक उपद्रव किया जा सकता है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जम्मू तथा काशमीर में बाहरी सहायता से उपद्रव करने वालों को उसी प्रकार कुचल दिया जायेगा जिस प्रकार वे भारत के किसी भी अन्य भाग में कुचल दिये जाते हैं।

विश्व सें स्थिति बहुत गम्भीर है। तनाव कम करने, युद्ध रोकने तथा शान्ति बनाए रखने के लिए भारत जो भी कर सकता है, लगातार करता रहेगा। हमारा यह दृष्टिकोण खोखले प्रदर्शनों से बिलक्कुल भिन्न है। इस प्रकार का काम करने के लिए तथा अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था दृढ़ रखनी होगी और देश में एकता पैदा करनी होगी।

मुझे आर्थिक संकट तथा विदेशी सम्बन्धों से भी अधिक इस बात की चिन्ता है कि देश में हिंसा जाग उठी है जिस से देश में जनतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। मैं इस सिद्धान्त का भी पूर्ण खंडन करती हूं कि देश में जनता में असन्तोष के कारण हिन्सात्मक घटनायें हो रही है, हम सभी जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जो आन्दोलन किये जाते हैं वह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। यहां पर तो कुछ लोगों ने पूर्ण समाज पर आंतक जमाया हुआ है और वे ही इस प्रकार की घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। यह बात देश के तथा हम सब के हित में है कि वे देश में ऐसी हिंसात्मक घटनायें न होने दें। हम अपने आप में विश्वास के कारण, अपनी नीतियों में विश्वास के कारण अपने कार्यक्रमों में विश्वास के कारण तथा इस महान देश की जनता में विश्सावस के कारण, हम विश्वास के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं।